

भारत में महँगाई और घरेलू उपभोग: खाद्य मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण डा० मनोज कुमार अवस्थी¹

¹सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, मानिकपुर, चित्रकूट उ०प्र०

Received: 20 July 2025, Accepted: 25 July 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2025

Abstract

भारत जैसे विकासशील एवं विशाल जनसंख्या वाले देश में महँगाई केवल व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से घरेलू कल्याण, खाद्य सुरक्षा, पोषण, वास्तविक आय, बचत, निवेश तथा जीवन-स्तर को प्रभावित करती है। विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव सामान्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक व्यापक और असमान होता है, क्योंकि निम्न एवं निम्न-मध्य आय वाले परिवार अपनी आय का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। वर्ष 2020–2024 की अवधि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए असाधारण रही। कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, श्रम एवं परिवहन संबंधी बाधाएँ, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में वृद्धि, रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता, प्रतिकूल मानसून एवं जलवायु घटनाएँ तथा घरेलू कृषि आपूर्ति में उतार-चढ़ाव ने खाद्य कीमतों पर लगातार दबाव बनाया। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य 2020 से 2024 के बीच भारत में खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग के संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23 एवं 2023–24 के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मुद्रास्फीति मापन, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तथा राष्ट्रीय आय के अपस्फीतिकारक के रूप में किया जाता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव केवल भोजन की लागत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवारों के गैर-खाद्य उपभोग को भी प्रभावित करता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ₹3,773 तथा शहरी भारत में ₹6,459 था। ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य का हिस्सा कुल औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का लगभग 46 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 39 प्रतिशत था। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023–24 में खाद्य का हिस्सा ग्रामीण भारत में 47.04 प्रतिशत और शहरी भारत में 39.68 प्रतिशत दर्ज हुआ। इससे स्पष्ट है कि खाद्य कीमतों में वृद्धि ग्रामीण परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति पर विशेष रूप से गंभीर प्रभाव डालती है। शोध में पाया गया कि 2020–21 में खाद्य मुद्रास्फीति कोविड-19 और आपूर्ति व्यवधानों के कारण ऊँची रही, 2021–22 में अपेक्षाकृत नरमी दिखाई दी, जबकि 2022–23 में वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट तथा घरेलू आपूर्ति दबावों ने पुनः मुद्रास्फीति को बढ़ाया। 2023–24 और 2024 में सब्जियों, दालों, मसालों, अंडों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव ने खाद्य मुद्रास्फीति को अत्यधिक अस्थिर बनाया। आरबीआई के अनुसार 2023–24 में समग्र मुद्रास्फीति में नरमी आई, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति आवर्ती आपूर्ति झटकों के कारण अस्थिर रही और चरम मौसम घटनाओं ने मूल्य-वृद्धि को बढ़ाया। अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का समाधान केवल मौद्रिक नीति के माध्यम से संभव नहीं है। कृषि उत्पादकता, भंडारण, शीत-शृंखला, बाजार सुधार, आपूर्ति शृंखला दक्षता, खाद्य प्रसंस्करण, लक्षित सामाजिक सुरक्षा,

पोषण कार्यक्रम, जलवायु-स्मार्ट कृषि तथा प्रभावी मूल्य सूचना प्रणाली को समन्वित रूप से मजबूत करना आवश्यक है।

प्रमुख शब्द— महँगाई, खाद्य मुद्रास्फीति, घरेलू उपभोग, वास्तविक आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, भारत।

Introduction

महँगाई आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक समस्याओं में से एक है। सामान्य अर्थ में महँगाई से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर में निरंतर वृद्धि से है। हालांकि सभी वस्तुओं की कीमतों में समान गति से वृद्धि नहीं होती। कुछ अवधियों में खाद्य, ईंधन या ऊर्जा जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्य कीमतों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में headline inflation अपेक्षाकृत नियंत्रित दिखाई दे सकती है, लेकिन परिवारों के वास्तविक जीवन-यापन की लागत में तीव्र वृद्धि हो सकती है। भारत में खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महत्वपूर्ण भार है। MoSPI के अनुसार वर्तमान CPI संरचना में Food & Beverag में का भार लगभग 45.86 प्रतिशत है, जिसमें Consumer Food Price Index का भार 39.05 प्रतिशत है। इसलिए खाद्य कीमतों में परिवर्तन समग्र ब् मुद्रास्फीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। खाद्य मुद्रास्फीति का सामाजिक प्रभाव आय-वर्गों के बीच समान नहीं होता। उच्च आय वाले परिवारों के बजट में भोजन का हिस्सा अपेक्षाकृत कम होता है। इसके विपरीत गरीब परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, विशेषकर अनाज, दाल, सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। अतः खाद्य कीमतों में वृद्धि उनकी वास्तविक आय को तेजी से कम करती है।

2020-2024 की अवधि में यह समस्या और अधिक जटिल हुई। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने उत्पादन, परिवहन, थोक एवं खुदरा बाजार तथा श्रम-आपूर्ति को प्रभावित किया। इसके बाद 2021-22 में वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के साथ ऊर्जा एवं कमोडिटी कीमतों में वृद्धि हुई। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक खाद्य, उर्वरक एवं ऊर्जा बाजारों पर दबाव बढ़ाया। भारत में 2022-23 के दौरान खाद्य एवं ईंधन कीमतों ने CPI को ऊपर बनाए रखा। तट ने भी इस अवधि में overlapping supply shocks, वैश्विक कमोडिटी कीमतों और युद्ध-संबंधी व्यवधानों को मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण कारणों के रूप में रेखांकित किया।

2023 और 2024 में स्थिति का स्वरूप कुछ बदला। व्यापक मुद्रास्फीति में अपेक्षाकृत नरमी के बावजूद खाद्य कीमतों में तीव्र अस्थिरता बनी रही। टमाटर, प्याज, आलू, दालें, मसाले, सब्जियाँ, दूध तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अलग-अलग समय पर तेज वृद्धि हुई। नवंबर 2024 में कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं में अत्यधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई; उदाहरण के लिए लहसुन, आलू, फूलगोभी और पत्तागोभी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इस पृष्ठभूमि में खाद्य मुद्रास्फीति को केवल कीमतों की समस्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह परिवारों के उपभोग व्यवहार को बदलती है। जब खाद्य बजट बढ़ता है तो परिवार कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन और अन्य गैर-खाद्य मदों पर व्यय कम कर सकते हैं। निम्न आय वाले परिवार भोजन

की मात्रा और गुणवत्ता में भी कटौती कर सकते हैं। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति का अध्ययन गरीबी, पोषण और मानव विकास के अध्ययन से सीधे जुड़ जाता है।

1.1 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व— इस अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होती है। पहला, भारत में खाद्य व्यय का घरेलू बजट में अत्यधिक महत्व है। HCES 2022–23 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में खाद्य मद का हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत और शहरी परिवारों में लगभग 39 प्रतिशत था। दूसरा, खाद्य मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से अधिक अस्थिर हो सकती है। RBI ने 2023–24 में भी खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता को recurring supply shocks और extreme weather events से जोड़ा। तीसरा, खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। ग्रामीण परिवार भोजन पर अधिक अनुपात खर्च करते हैं, जबकि शहरी परिवारों के खाद्य बजट में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दूध, सब्जियाँ तथा तैयार भोजन की भूमिका अधिक हो सकती है। चौथा, खाद्य कीमतों में वृद्धि वास्तविक आय को कम करती है। यदि नाममात्र आय 5 प्रतिशत बढ़ती है लेकिन खाद्य कीमतें 10 प्रतिशत बढ़ती हैं, तो परिवार की वास्तविक खाद्य क्रय-शक्ति घट सकती है। पाँचवाँ, खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव पोषण पर पड़ सकता है। परिवार महँगे प्रोटीन स्रोतों जैसे दाल, अंडे, दूध एवं मांस की जगह सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं। छठा, खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव बचत और निवेश पर भी पड़ता है। आवश्यक उपभोग पर अधिक खर्च होने से विवेकाधीन बचत घट सकती है।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य— प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. 2020–2024 के दौरान भारत में सामान्य CPI तथा खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
2. खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख निर्धारकों की पहचान करना।
3. खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी परिवारों पर खाद्य मुद्रास्फीति के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
5. खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।
6. खाद्य मुद्रास्फीति के कारण गैर-खाद्य उपभोग में संभावित परिवर्तन का अध्ययन करना।
7. खाद्य मुद्रास्फीति के पोषण एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रभावों का विश्लेषण करना।
8. कोविड-19 और वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
9. 2022–23 एवं 2023–24 HCES के माध्यम से घरेलू उपभोग संरचना का विश्लेषण करना।
10. भारत की मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों का मूल्यांकन करना।
11. खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु नीति-स्तरीय सुझाव प्रस्तुत करना।

1.3 शोध प्रश्न— अध्ययन निम्न शोध प्रश्नों का उत्तर खोजता है—

1. 2020–2024 के दौरान भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति क्या रही?
2. क्या खाद्य मुद्रास्फीति सामान्य ब् मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर रही?
3. खाद्य मुद्रास्फीति ने घरेलू वास्तविक क्रय-शक्ति को किस प्रकार प्रभावित किया?
4. क्या ग्रामीण परिवार खाद्य मुद्रास्फीति से शहरी परिवारों की अपेक्षा अधिक प्रभावित हुए?
5. क्या खाद्य कीमतों में वृद्धि से गैर-खाद्य उपभोग में कमी आती है?

6. खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख आपूर्ति-पक्षीय निर्धारक कौन-से रहे?
7. जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाओं ने खाद्य कीमतों की अस्थिरता को किस सीमा तक बढ़ाया?
8. सरकारी खाद्य एवं आपूर्ति प्रबंधन उपाय कितने प्रभावी रहे?
9. खाद्य मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मौद्रिक नीति और राजकोषीय/प्रशासनिक नीति की तुलनात्मक भूमिका क्या रही?

1.4 परिकल्पनाएँ—

1. खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग व्यय के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
2. खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग व्यय के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।
3. खाद्य मुद्रास्फीति का ग्रामीण एवं शहरी परिवारों पर समान प्रभाव पड़ता है।
4. खाद्य मुद्रास्फीति का ग्रामीण परिवारों पर शहरी परिवारों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है।
5. खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि गैर-खाद्य उपभोग को प्रभावित नहीं करती।
6. खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि गैर-खाद्य उपभोग को कम करती है।
7. खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता मुख्यतः मांग-पक्षीय कारकों से निर्धारित होती है।
8. खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता में आपूर्ति-पक्षीय, जलवायु एवं वैश्विक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.5 शोध प्राविधि— प्रस्तुत अध्ययन में भारत में महँगाई एवं घरेलू उपभोग पर खाद्य मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक शोध प्राविधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की समयावधि 2020 से 2024 तक निर्धारित की गई है, क्योंकि यह अवधि कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, वैश्विक आपूर्ति-शृंखला व्यवधान, रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा एवं खाद्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में महँगाई की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसके लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, Household Consumption Expenditure Survey -HCES, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, FAO तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रों और पुस्तकों से प्राप्त आँकड़ों एवं सूचनाओं का उपयोग किया गया है। अध्ययन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति, ग्रामीण एवं शहरी उपभोग व्यय, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, खाद्य एवं गैर-खाद्य व्यय की हिस्सेदारी तथा वास्तविक क्रय-शक्ति को प्रमुख विश्लेषणात्मक संकेतकों के रूप में चुना गया है। खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को समझने के लिए 2020-2024 के दौरान उपलब्ध वार्षिक एवं मासिक ब्य तथा ब्य आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही HCES 2022-23 एवं 2023-24 के आँकड़ों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी परिवारों की उपभोग संरचना का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न वर्षों में खाद्य एवं गैर-खाद्य व्यय के अनुपात में हुए परिवर्तन को प्रतिशत तथा तुलनात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन में खाद्य मुद्रास्फीति के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत कोविड-19 महामारी, आपूर्ति-शृंखला व्यवधान, कृषि उत्पादन में परिवर्तन, मानसून एवं जलवायु संबंधी घटनाएँ, वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें, परिवहन लागत, सरकारी खाद्य नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा मौद्रिक नीति जैसे कारकों का अध्ययन किया गया है। मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिशत परिवर्तन, प्रवृत्ति विश्लेषण, ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक विश्लेषण तथा खाद्य एवं गैर-खाद्य उपभोग के अनुपात का अध्ययन किया गया है। खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए नाममात्र एवं वास्तविक उपभोग की अवधारणा का उपयोग किया गया है। शोध में यह मान्यता अपनाई गई है कि यदि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और परिवार की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो परिवार की वास्तविक क्रय-शक्ति में कमी आती है तथा कुल बजट में खाद्य व्यय की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप गैर-खाद्य वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा बचत पर व्यय प्रभावित हो सकता है। इस संबंध को समझने के लिए उपभोक्ता बजट की अवधारणा तथा एंगेल के नियम को सैद्धांतिक आधार बनाया गया है। ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के खाद्य व्यय की हिस्सेदारी में अंतर के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति के असमान प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता आधिकारिक सरकारी स्रोतों को दी गई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का परस्पर मिलान किया गया है तथा जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ तट और MoSPI द्वारा प्रकाशित संशोधित आँकड़ों को आधार बनाया गया है। अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़ों को सारणीबद्ध करके उनकी प्रवृत्तियों, समानताओं एवं अंतरों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार शोध प्राविधि का उद्देश्य केवल खाद्य मुद्रास्फीति की दर को मापना नहीं है, बल्कि उसके घरेलू उपभोग, वास्तविक आय, क्रय-शक्ति, बचत, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण-शहरी आर्थिक असमानताओं पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को समग्र रूप से समझना है।

1.6 तथ्य-संकलन के स्रोत- प्रस्तुत अध्ययन के लिए तथ्य एवं आँकड़े मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों से संकलित किए गए हैं। अध्ययन की विषय-वस्तु के अनुरूप भारत में महँगाई, खाद्य मुद्रास्फीति तथा घरेलू उपभोग से संबंधित आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, मौद्रिक नीति संबंधी प्रकाशन, Handbook of Statistics on Indian Economy तथा CPI संबंधी समय-शृंखला आँकड़ों का उपयोग किया गया है। RBI के आँकड़ों में 2020-21 से 2024-25 तक CPI के सामान्य तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह के मासिक सूचकांक उपलब्ध हैं, जिससे अध्ययन अवधि में मूल्य-परिवर्तन की प्रवृत्ति का विश्लेषण संभव होता है।

घरेलू उपभोग के अध्ययन के लिए National Statistical Office द्वारा संचालित Household Consumption Expenditure Survey 2022-23 एवं 2023-24 को प्रमुख आधार बनाया गया है। HCES का उद्देश्य परिवारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए जाने वाले उपभोग व्यय की जानकारी प्राप्त करना है तथा इसके आँकड़ों का उपयोग आर्थिक कल्याण, गरीबी, असमानता और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भार निर्धारित करने में

भी किया जाता है। HCES 2023–24 में देशभर के 2,61,953 परिवारों से आँकड़े संकलित किए गए, जिनमें 1,54,357 ग्रामीण तथा 1,07,596 शहरी परिवार शामिल थे।

अध्ययन में आर्थिक एवं नीतिगत संदर्भ के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित Economic Survey, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि उत्पादन संबंधी आँकड़े तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया है। अंतरराष्ट्रीय तुलना एवं वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए [World Bank] International Monetary Fund - IMF Food and Agriculture Organization-FAO तथा OECD के प्रकाशनों का संदर्भ लिया गया है।

इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित शोध-पत्र, शोध-प्रबंध, पुस्तकें, RBI Bulletin, Economic and Political Weekly में प्रकाशित शोध, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल तथा विश्वसनीय अकादमिक डेटाबेस से प्राप्त साहित्य का उपयोग किया गया है। संकलित आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता आधिकारिक सरकारी स्रोतों को दी गई है तथा विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध समान सूचकों का यथासंभव तुलनात्मक सत्यापन किया गया है। इस प्रकार तथ्य-संकलन की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि 2020–2024 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग में हुए परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके।

1.7 साहित्य समीक्षा— भारत में महंगाई और खाद्य मुद्रास्फीति पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य कीमतों की भूमिका को समझने वाले प्रारंभिक अध्ययनों में कृषि उत्पादन, आपूर्ति की अनिश्चितता, मांग में परिवर्तन तथा सरकारी मूल्य नीतियों को प्रमुख कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है। समय के साथ इस साहित्य में वैश्विक कमोडिटी कीमतों, ऊर्जा कीमतों, विनिमय दर, आपूर्ति शृंखला, जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता व्यवहार को भी शामिल किया गया है। ऋणसंजप और पदप ने भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के अध्ययन में कृषि आपूर्ति, मांग तथा सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों की भूमिका पर बल दिया। उनके अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केवल मौद्रिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।

Bhattacharya एवं Sengupta ने भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों के कारकों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आय में वृद्धि, बदलती खाद्य आदतें तथा कृषि आपूर्ति की सीमाएँ खाद्य कीमतों पर दबाव उत्पन्न कर सकती हैं। RBI के शोध साहित्य में खाद्य मुद्रास्फीति की आपूर्ति-शृंखला संबंधी व्याख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। RBI Bulletin में प्रकाशित Supply Chain Dynamics and Food Inflation in India अध्ययन ने किसान से उपभोक्ता तक की मूल्य-शृंखला का विश्लेषण करते हुए पाया कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं में किसान को प्राप्त उपभोक्ता के रुपये का हिस्सा काफी अलग-अलग है तथा सड़क, मंडी अवसंरचना, सूचना प्रवाह और सिंचाई जैसी सुविधाएँ आपूर्ति-शृंखला की दक्षता बढ़ाकर मूल्य-वृद्धि को कम करने में सहायता कर सकती हैं। कोविड-19 महामारी से संबंधित अध्ययनों में यह सामने आया कि 2020 के दौरान लॉकडाउन ने उत्पादन की अपेक्षा खाद्य वस्तुओं की आवाजाही, श्रम उपलब्धता, परिवहन, मंडी गतिविधियों तथा खुदरा वितरण को अधिक प्रभावित किया। इससे कुछ खाद्य वस्तुओं में स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 2022 के बाद उपलब्ध साहित्य में रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा कीमतों, उर्वरक लागत तथा खाद्य तेलों

एवं अन्य कृषि वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय खाद्य बाजार पूर्णतः घरेलू परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि वैश्विक बाजारों से भी प्रभावित होता है।

हाल के अध्ययनों में जलवायु परिवर्तन और खाद्य मुद्रास्फीति का संबंध भी महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। अत्यधिक तापमान, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा तथा अन्य मौसमी घटनाएँ कृषि उत्पादन में अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से सब्जियों एवं शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज में इसका प्रभाव कीमतों पर तत्काल दिखाई देता है। घरेलू उपभोग से संबंधित साहित्य में Engel's Law अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार आय बढ़ने के साथ भोजन पर होने वाले कुल व्यय का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन कुल उपभोग व्यय में भोजन की हिस्सेदारी सामान्यतः कम होती जाती है। भारत के HCES आँकड़े इस सिद्धांत को समझने के लिए उपयोगी आधार प्रदान करते हैं। HCES 2023–24 के अनुसार ग्रामीण भारत में भोजन का हिस्सा औसत डब्ब का 47.04 प्रतिशत तथा शहरी भारत में 39.68 प्रतिशत था।

HCES 2023–24 से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण परिवारों के खाद्य व्यय में beverages, refreshments and processed food का हिस्सा 9.84 प्रतिशत, दूध एवं दुग्ध उत्पादों का 8.44 प्रतिशत तथा सब्जियों का 6.03 प्रतिशत था। शहरी परिवारों में इन मदों के हिस्से क्रमशः 11.09 प्रतिशत, 7.19 प्रतिशत और 4.12 प्रतिशत थे।

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध खाद्य मुद्रास्फीति के निर्धारकों, कृषि आपूर्ति तथा मौद्रिक नीति पर केंद्रित हैं, जबकि 2020–2024 की विशिष्ट अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति और घरेलू उपभोग संरचना के संयुक्त अध्ययन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। प्रस्तुत शोध इसी अंतर को कम करने का प्रयास करता है। इसमें कोविड-19, वैश्विक आपूर्ति झटकों, खाद्य कीमतों की अस्थिरता तथा HCES द्वारा उपलब्ध घरेलू उपभोग आँकड़ों को एक समग्र विश्लेषणात्मक ढाँचे में रखा गया है।

1.8 डेटा विश्लेषण— प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आँकड़ों का विश्लेषण मुख्यतः वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं प्रवृत्ति-आधारित पद्धति से किया गया है। 2020–2024 की अवधि में CPI तथा खाद्य मुद्रास्फीति के परिवर्तन को समझने के लिए वर्षवार तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ मासिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। RBI के CPI आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि में सामान्य CPI तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के मूल्य सूचकांकों में निरंतर वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए CPI Combined का सूचकांक 2020–21 में लगभग 151.4 के स्तर से बढ़कर 2023–24 में लगभग 185.8 तक पहुँच गया, जबकि खाद्य एवं पेय पदार्थों का सूचकांक इसी अवधि में लगभग 154.0 से बढ़कर 190.7 तक पहुँचा।

मुद्रास्फीति की वार्षिक प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 2020–21 में ग्रामीण CPI inflation कई महीनों में 7 प्रतिशत से अधिक रही। 2022–23 में ग्रामीण CPI inflation अप्रैल में 8.4 प्रतिशत तथा मई में 7.1 प्रतिशत रही और वर्ष के अन्य महीनों में भी यह अपेक्षाकृत ऊँचे स्तर पर बनी रही। 2023–24 में कुछ महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आई, लेकिन जुलाई में ग्रामीण ब्ब पदसिंजपवद 7.6 प्रतिशत तक पहुँची। खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में 2023–24 विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। खाद्य एवं पेय पदार्थों के CPI सूचकांक में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। अप्रैल 2023 में इसका

सूचकांक 177.9 था, जो जुलाई में 193.5 तक पहुँचा और मार्च 2024 में 190.7 रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि खाद्य कीमतों की अस्थिरता मिनकसपदम पदसिंजपवद की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती है।

घरेलू उपभोग के संदर्भ में भू 2023–24 के आँकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण भारत में औसत MPCE ₹4,122 तथा शहरी भारत में ₹6,996 रहा। ग्रामीण परिवारों के कुल उपभोग में खाद्य मदों की हिस्सेदारी 47.04 प्रतिशत तथा शहरी परिवारों में 39.68 प्रतिशत रही।

तालिका-01

HCES 2023–24 के आधार पर घरेलू उपभोग की संरचना

क्र०	मद	ग्रामीण भारत	शहरी भारत
1	औसत MPCE (₹)	4,122	6,996
2	खाद्य व्यय (₹)	1,939	2,776
3	खाद्य व्यय का हिस्सा (%)	47.04	39.68
4	गैर-खाद्य व्यय (₹)	2,183	4,220
5	गैर-खाद्य व्यय का हिस्सा (%)	52.96	60.32

स्रोत— HCES 2023–24, MoSPI-

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवारों की उपभोग संरचना खाद्य कीमतों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील है। ग्रामीण परिवार अपनी कुल उपभोग क्षमता का लगभग आधा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं। इसके विपरीत शहरी परिवारों में खाद्य व्यय का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है और गैर-खाद्य व्यय का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है।

खाद्य समूहों के भीतर भी पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। ग्रामीण परिवारों में beverages, refreshments एवं processed food का हिस्सा 9.84 प्रतिशत, दूध एवं दुग्ध उत्पादों का 8.44 प्रतिशत तथा सब्जियों का 6.03 प्रतिशत है। शहरी परिवारों में processed विवक एवं beverages का हिस्सा 11.09 प्रतिशत, दूध एवं दुग्ध उत्पादों का 7.19 प्रतिशत तथा सब्जियों का 4.12 प्रतिशत है।

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को केवल समग्र खाद्य मूल्य सूचकांक से नहीं समझा जा सकता। विभिन्न आय एवं क्षेत्रीय समूहों की consumption basket अलग-अलग होती है। इसलिए किसी एक national inflation rate से सभी परिवारों पर पड़ने वाले वास्तविक आर्थिक दबाव को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।

1.9 चर्चा – 2020–2024 की अवधि के आँकड़ों और उपलब्ध साहित्य के संयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति बहुआयामी प्रकृति की समस्या है। इसका संबंध केवल मांग में वृद्धि से नहीं है, बल्कि कृषि उत्पादन, आपूर्ति-शृंखला, परिवहन, भंडारण, मौसम, वैश्विक कीमतों, ऊर्जा लागत तथा सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपों से भी है। 2020 में कोविड-19 महामारी ने खाद्य बाजारों को एक असाधारण आपूर्ति झटका दिया। लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादन जारी रहने के बावजूद श्रम, परिवहन, मंडी, थोक

व्यापार और खुदरा वितरण में व्यवधान उत्पन्न हुए। परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में उत्पादन उपलब्ध होने के बावजूद उपभोक्ता बाजार तक उसकी आपूर्ति सामान्य रूप से नहीं पहुँच सकी। इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा केवल पर्याप्त कृषि उत्पादन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कुशल आपूर्ति-शृंखला भी उतनी ही आवश्यक है। 2022 में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या को और जटिल किया। ऊर्जा, उर्वरक, खाद्य तेल तथा अन्य कृषि पदचनजे की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव उत्पादन लागत के माध्यम से घरेलू खाद्य कीमतों पर पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति का एक हिस्सा वैश्विक मूल्य-चक्र से भी जुड़ा हुआ है।

2023-24 के दौरान खाद्य कीमतों की अस्थिरता ने एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या को उजागर किया। सब्जियों, दालों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि ने यह प्रदर्शित किया कि उत्पादन में मामूली कमी भी अपर्याप्त भंडारण और कमजोर आपूर्ति के कारण खुदरा कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर सकती है। आर0बी0आई0 के आपूर्ति संबंधी अध्ययन में भी कृषि बाजार की दक्षता, सड़क एवं मंडी अवसंरचना, सूचना प्रवाह और सिंचाई को **farm&gate ls retail price** तक के अंतर को कम करने के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है।

घरेलू उपभोग के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण है। HCES 2023-24 के अनुसार ग्रामीण परिवारों के कुल उपभोग व्यय में खाद्य का हिस्सा 47.04 प्रतिशत है, जबकि शहरी परिवारों में यह 39.68 प्रतिशत है। अतः यदि खाद्य कीमतों में समान प्रतिशत वृद्धि होती है, तो ग्रामीण परिवारों के बजट पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव पड़ने की संभावना रहती है।

इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम व्यय-विस्थापन प्रभाव है। खाद्य पदार्थ महँगे होने पर परिवारों को भोजन पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। यदि आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, मनोरंजन, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं अथवा बचत पर व्यय घटा सकते हैं। HCES 2023-24 में ग्रामीण परिवारों के गैर-खाद्य व्यय का हिस्सा लगभग 53 प्रतिशत और शहरी परिवारों में लगभग 60 प्रतिशत रहा। इसलिए खाद्यान्न मंहगाई के लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में गैर-खाद्य मांग और घरेलू बचत पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

खाद्य मुद्रास्फीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पोषण प्रभाव है। खाद्य कीमतों में वृद्धि होने पर निम्न आय वाले परिवार महँगे प्राटीन, मंहगे खाने, फल, दूध तथा अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की मात्रा कम कर सकते हैं। इससे ऊष्मांक ग्रहण में तत्काल बड़ी कमी न दिखाई देने पर भी आहार में विविधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति को केवल CPI के संदर्भ में नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

ग्रामीण परिवारों के संदर्भ में स्थिति कुछ अधिक जटिल है क्योंकि वे एक साथ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ने पर बाजार योग्य अधिशेष रखने वाले किसान लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन छोटे किसान, सीमांत किसान, कृषि मजदूर और भूमिहीन परिवारों को समान लाभ नहीं मिलता। अतः खाद्य मुद्रास्फीति के वितरणात्मक प्रभावों का अध्ययन करते समय परिवार की उत्पादन एवं आय संरचना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नीतिगत दृष्टि से अध्ययन यह संकेत देता है कि केवल

मौद्रिक नीति के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति का समाधान संभव नहीं है। ब्याज दरों में परिवर्तन 'हहतमहंजम' कमउंदक को प्रभावित कर सकता है, लेकिन टमाटर, प्याज, सब्जियों या दालों की आपूर्ति की कमी को प्रत्यक्ष रूप से दूर नहीं कर सकता। इसलिए मौद्रिक नीति के साथ कृषि आपूर्ति प्रबंधन, बफर स्टॉक, भंडारण, कोल्ड चेन, सिंचाई, फसल विविधीकरण, बाजार एकीकरण और लक्षित खाद्य सुरक्षा उपाय का समन्वय आवश्यक है।

अंततः यह चर्चा इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति एक समष्टि आर्थिक समस्या के साथ-साथ घरेलू कल्याण की समस्या भी है। खाद्य कीमतों में स्थिरता से केवल CPI नियंत्रित नहीं होता, बल्कि परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति, उपभोग क्षमता, पोषण, बचत और जीवन-स्तर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए भविष्य की महंगाई-रोधी रणनीति को मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आय-सुरक्षा को एकीकृत करके आगे बढ़ाना चाहिए।

1.10 विवेचना- भारत में महंगाई और घरेलू उपभोग के बीच संबंध का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति केवल कीमतों में वृद्धि की समस्या नहीं है, बल्कि यह परिवारों की वास्तविक आय, क्रय-शक्ति, उपभोग संरचना, बचत, पोषण तथा जीवन-स्तर को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 2020-2024 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, वैश्विक आपूर्ति-शृंखला व्यवधान, रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा एवं उर्वरक कीमतों में वृद्धि तथा प्रतिकूल मौसम जैसी अनेक परिस्थितियों का सामना किया। इन सभी कारकों ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न की।

वर्ष 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण मांग की तुलना में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएँ थीं। लॉकडाउन के कारण कृषि उत्पादन की तुलना में कृषि उत्पादों के परिवहन, मंडी संचालन, श्रम की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावित हुई। इससे अनेक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में क्षेत्रीय एवं समयगत असंतुलन उत्पन्न हुआ। इस स्थिति ने यह स्पष्ट किया कि खाद्य मूल्य स्थिरता के लिए पर्याप्त उत्पादन के साथ-साथ कुशल आपूर्ति-शृंखला भी आवश्यक है।

वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों के पुनः आरंभ होने के साथ बाजारों में सुधार हुआ, किंतु वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, खाद्य तेल, उर्वरक तथा अन्य कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि ने घरेलू कीमतों पर दबाव बनाए रखा। वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को और बढ़ाया। भारत में इसका प्रभाव खाद्य तेल, गेहूँ, उर्वरक, परिवहन तथा कृषि लागत के माध्यम से दिखाई दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति अब केवल घरेलू कृषि उत्पादन से निर्धारित नहीं होती, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है।

वर्ष 2023 और 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रकृति अधिक अस्थिर रही। विशेष रूप से सब्जियों, दालों, मसालों तथा कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई। प्रतिकूल मानसून, अत्यधिक तापमान, बाढ़ एवं अन्य मौसम संबंधी घटनाओं ने उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित किया। फलतः खाद्य कीमतों में अल्प अवधि में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक निर्धारक बन सकता है।

घरेलू उपभोग के संदर्भ में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। HCES 2023–24 के अनुसार ग्रामीण भारत में कुल औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में खाद्य का हिस्सा 47.04 प्रतिशत था, जबकि शहरी भारत में यह 39.68 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवारों का बजट खाद्य कीमतों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर ग्रामीण परिवारों को अपने सीमित बजट का अधिक हिस्सा भोजन पर खर्च करना पड़ता है। इस स्थिति को एंगेल के नियम के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। सामान्यतः निम्न आय वाले परिवार अपनी आय का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव आय के निचले वर्गों पर अधिक पड़ता है। उच्च आय वाले परिवार खाद्य कीमतों में वृद्धि को अपेक्षाकृत आसानी से समायोजित कर सकते हैं, जबकि निम्न आय वाले परिवारों के पास व्यय को समायोजित करने के सीमित विकल्प होते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति के कारण परिवारों में व्यय–विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भोजन पर अधिक खर्च होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, मनोरंजन, परिवहन, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं तथा बचत पर व्यय कम किया जा सकता है। लंबे समय तक खाद्य मुद्रास्फीति बने रहने पर यह प्रभाव मानव पूँजी निर्माण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का पोषण संबंधी प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। निम्न आय वाले परिवार महँगे खाद्य पदार्थों, विशेषकर दाल, दूध, अंडे, फल तथा अन्य पोषक खाद्य पदार्थों का सेवन कम करके अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य विकल्पों की ओर जा सकते हैं। इससे भोजन की मात्रा बनी रहने पर भी उसकी गुणवत्ता एवं विविधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के बीच खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव समान नहीं है। ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय की हिस्सेदारी अधिक होने के कारण वे खाद्य मूल्य वृद्धि से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कृषि उत्पादक परिवारों को कुछ परिस्थितियों में बढ़ी हुई कृषि कीमतों से आय लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह लाभ सभी किसानों को समान रूप से नहीं मिलता। छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति के वितरणात्मक प्रभावों को आय, रोजगार और कृषि–उत्पादन की स्थिति के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है। सरकारी नीतियों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, खुले बाजार बिक्री, आयात–निर्यात नीति, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता तथा विभिन्न सब्सिडी उपायों ने खाद्य कीमतों के प्रभाव को सीमित करने में सहायता की है। फिर भी दीर्घकालीन समाधान के लिए कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, कोल्ड–चेन, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार एकीकरण को मजबूत करना आवश्यक है। समग्र रूप से विवेचना से स्पष्ट होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति एक बहुआयामी आर्थिक समस्या है। इसका संबंध कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, जलवायु, वैश्विक बाजार, मौद्रिक नीति तथा सामाजिक सुरक्षा से है। अतः इसके समाधान के लिए समन्वित एवं दीर्घकालीन नीति दृष्टिकोण आवश्यक है।

1.11 परिणाम— प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए हैं—

✚ खाद्य मुद्रास्फीति भारतीय महँगाई का प्रमुख घटक रही है। 2020–2024 के दौरान कई अवधियों में खाद्य मुद्रास्फीति सामान्य CPI मुद्रास्फीति से अधिक रही।

- ✚ 2020 में आपूर्ति-पक्षीय कारक प्रमुख रहे। कोविड-19 लॉकडाउन ने परिवहन, श्रम, मंडी और वितरण व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसके कारण खाद्य कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव हुआ।
- ✚ 2022 में वैश्विक कारकों का प्रभाव बढ़ा। रूस-यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा कीमतों, उर्वरक लागत और वैश्विक खाद्य बाजार की अस्थिरता ने भारतीय खाद्य कीमतों को प्रभावित किया।
- ✚ 2023-2024 में खाद्य मुद्रास्फीति अत्यधिक अस्थिर रही। सब्जियों, दालों, मसालों तथा अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ाया।
- ✚ ग्रामीण परिवार खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। HCES 2023-24 में ग्रामीण परिवारों के कुल उपभोग व्यय में खाद्य का हिस्सा 47.04 प्रतिशत था, जबकि शहरी परिवारों में यह 39.68 प्रतिशत था।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति वास्तविक क्रय-शक्ति को प्रभावित करती है। यदि आय में वृद्धि खाद्य कीमतों की वृद्धि से कम हो, तो परिवार की वास्तविक उपभोग क्षमता घट जाती है।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति गैर-खाद्य उपभोग को प्रभावित कर सकती है। भोजन पर अधिक खर्च होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, मनोरंजन और अन्य मदों पर व्यय कम होने की संभावना रहती है।
- ✚ निम्न आय वर्ग पर प्रभाव अधिक गंभीर है। इन परिवारों के बजट में भोजन की हिस्सेदारी अधिक होने के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि का वास्तविक आर्थिक प्रभाव अधिक होता है।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति पोषण को प्रभावित कर सकती है। महँगी दाल, दूध, अंडे, फल एवं सब्जियों की खपत में कमी से भोजन की गुणवत्ता और आहार में विविधता प्रभावित हो सकती है।
- ✚ जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएँ महत्वपूर्ण निर्धारक बन रही हैं। अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढ़ एवं सूखे से कृषि उत्पादन प्रभावित होने पर खाद्य कीमतों में तेजी आ सकती है।
- ✚ आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरी कीमतों में उतार-चढ़ाव को बढ़ाती है। पर्याप्त उत्पादन के बावजूद स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड चेन की कमी से उपभोक्ता कीमतों में तीव्र वृद्धि हो सकती है।
- ✚ मौद्रिक नीति अकेले खाद्य मुद्रास्फीति का समाधान नहीं कर सकती। खाद्य मुद्रास्फीति के बड़े हिस्से का संबंध आपूर्ति पक्ष के झटके से होने के कारण कृषि एवं आपूर्ति प्रबंधन आवश्यक है।
- ✚ PDS और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हैं। गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले/मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने से खुले बाजार की खाद्य कीमतों का प्रभाव कम किया जा सकता है।
- ✚ ग्रामीण एवं शहरी उपभोग संरचना में स्पष्ट अंतर है। ग्रामीण परिवारों का खाद्य व्यय अनुपात अधिक है, जबकि शहरी परिवारों में गैर-खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं का हिस्सा अधिक है।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव केवल वर्तमान उपभोग तक सीमित नहीं है। लंबे समय तक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति रहने पर घरेलू बचत, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव पूँजी निर्माण पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या संरचनात्मक भी है। कृषि उत्पादकता, बाजार संरचना, भंडारण, सिंचाई, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण में सुधार के बिना दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता कठिन है।

- ✚ वैश्विक एवं घरेलू कारकों का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय खाद्य कीमतें अब केवल घरेलू कृषि उत्पादन से निर्धारित नहीं होतीं; वैश्विक ऊर्जा, खाद्य एवं उर्वरक कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति का वितरणात्मक प्रभाव असमान है। सभी परिवार समान उपभोग टोकरी नहीं रखते, इसलिए राष्ट्रीय औसत CPI अलग-अलग आय वर्गों के वास्तविक महंगाई का अनुभव को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं करता।
- ✚ खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय नीति आवश्यक है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण, व्यापार, मौद्रिक नीति और सामाजिक सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
- ✚ भविष्य की नीति में जलवायु-सहनीय कृषि को प्राथमिकता देनी होगी। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लचीली फसलें, कुशल सिंचाई, फसल विविधीकरण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष— भारत में महंगाई और घरेलू उपभोग के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 2020–2024 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था और परिवारों के आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौती रही। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपूर्ति व्यवधानों से लेकर वैश्विक भू-राजनीतिक संकट, ऊर्जा एवं उर्वरक कीमतों में वृद्धि तथा प्रतिकूल मौसम तक अनेक कारकों ने खाद्य कीमतों को प्रभावित किया। इस अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति की प्रकृति केवल मांग-आधारित नहीं रही, बल्कि आपूर्ति-पक्षीय और संरचनात्मक कारकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दी। अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव विभिन्न आय एवं सामाजिक समूहों पर समान नहीं पड़ता। ग्रामीण परिवारों के कुल उपभोग व्यय में खाद्य का हिस्सा शहरी परिवारों की तुलना में अधिक होने के कारण ग्रामीण एवं निम्न आय परिवार अधिक संवेदनशील पाए गए। खाद्य कीमतों में वृद्धि से उनकी वास्तविक क्रय-शक्ति प्रभावित होती है तथा परिवारों को अपने सीमित बजट का अधिक हिस्सा भोजन पर खर्च करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप गैर-खाद्य उपभोग, बचत, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय प्रभावित हो सकते हैं।

अतः भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को केवल CPI या CFPI के एक समष्टि आर्थिक सूचक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह आय-वितरण, गरीबी, पोषण, खाद्य सुरक्षा, मानव विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी व्यापक समस्या है। दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक भंडारण एवं कोल्ड-चेन, कुशल परिवहन, बाजार एकीकरण, जलवायु-स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत की भविष्य की महंगाई-रोधी रणनीति का आधार केवल “मूल्य स्थिरता” नहीं, बल्कि “मूल्य स्थिरता के साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और वास्तविक आय की सुरक्षा” होना चाहिए। यही दृष्टिकोण समावेशी, सतत एवं जन-केंद्रित आर्थिक विकास के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

अनुशंसाएँ—

1. कृषि उत्पादकता में वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घकाल में नियंत्रित करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. भंडारण एवं कोल्ड-चेन का विस्तारकृफल, सब्जियों, आलू, प्याज, दूध तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण एवं आधुनिक कोल्ड-चेन नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन के बाद होने वाली क्षति और कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके।
3. कृषि आपूर्ति-शृंखला को मजबूत करना, किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों की आपूर्ति में अनावश्यक मध्यवर्ती लागत को कम करने के लिए परिवहन, मंडी, डिजिटल व्यापार तथा प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
4. दालों एवं खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन, उत्पादकता एवं प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।
5. जलवायु-स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ एवं अत्यधिक तापमान जैसी घटनाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जलवायु-सहनीय फसलों, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और मौसम आधारित कृषि सलाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. रियल-टाइम खाद्य मूल्य निगरानी प्रणाली, केंद्र एवं राज्य सरकारों को डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मौसम संबंधी आँकड़ों तथा बाजार सूचना के आधार पर ऐसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जो संभावित खाद्य मूल्य-वृद्धि का समय रहते संकेत दे सके।
7. बफर स्टॉक प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना, गेहूँ, चावल, दालों, प्याज आदि आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग, उत्पादन एवं कीमतों के पूर्वानुमान के आधार पर गतिशील बफर स्टॉक नीति अपनाई जानी चाहिए।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, खाद्य मुद्रास्फीति के समय गरीब एवं कमजोर परिवारों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चूने की पहुंच, पारदर्शिता, पोर्टेबिलिटी और डिजिटल निगरानी को और मजबूत किया जाना चाहिए।
9. निम्न आय परिवारों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा, अत्यधिक खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति में कमजोर आय-वर्गों को लक्षित खाद्य सहायता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अथवा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
10. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, कृषि उपज के प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं संरक्षण की क्षमता बढ़ाने से फसल कटाई के बाद का नुकसान कम किए जा सकते हैं तथा खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पूरे वर्ष सुनिश्चित की जा सकती है।
11. मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समन्वय, खाद्य मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति-पक्षीय होने की स्थिति में केवल मौद्रिक नीति पर निर्भर रहने के बजाय, आर0बी0आई0 तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर नीति-समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
12. पोषण-संवेदी मुद्रास्फीति नीति, महंगाई नियंत्रण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दाल, दूध, अंडे, फल एवं सब्जियों जैसे पोषक खाद्य पदार्थ निम्न आय परिवारों की पहुंच से बाहर न हों। खाद्य मूल्य नीति को पोषण सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए।

13. ग्रामीण आय एवं रोजगार को मजबूत करना, ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आय बढ़ाने, कृषि जोखिम कम करने तथा गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का विस्तार करने से खाद्य कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों की क्रय-शक्ति तथा आर्थिक सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी।

सन्दर्भ सूची—

- 1- Asian Development Bank. (2024). *Asian Development Outlook 2024*. Manila: Asian Development Bank.
- 2- Bhattacharya, R., & Sengupta, A. (2013). Food inflation in India: Causes and policy responses. *Economic & Political Weekly*.
- 3- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics*. Pearson Education.
- 4- Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2016). Growth, urbanization and poverty reduction in India. Washington, DC: World Bank.
- 5- Food and Agriculture Organization. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023*. Rome: FAO.
- 6- Food and Agriculture Organization. (2024). *FAO Food Price Index*. Rome: FAO.
- 7- Gulati, A., & Saini, S. (2013). *Taming Food Inflation in India*. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER).
- 8- Government of India. (2023). *Economic Survey 2022-23*. Ministry of Finance, New Delhi.
- 9- Government of India. (2024). *Economic Survey 2023-24*. Ministry of Finance, New Delhi.
- 10- Government of India. (2025). *Economic Survey 2024-25*. Ministry of Finance, New Delhi.
- 11- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*. Washington, DC: IMF.
- 12- Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2023). *Household Consumption Expenditure Survey 2022-23: Fact Sheet*. Government of India, New Delhi.
- 13- Reserve Bank of India. (2022). *Annual Report 2021-22*. Mumbai: Reserve Bank of India.
- 14- Reserve Bank of India. (2023). *Annual Report 2022-23*. Mumbai: Reserve Bank of India.
- 15- Reserve Bank of India. (2024). *Annual Report 2023-24*. Mumbai: Reserve Bank of India.
- 16- Reserve Bank of India. (2024). *Handbook of Statistics on Indian Economy 2023-24*. Mumbai: RBI.
- 17- Reserve Bank of India. (2024). *Report on Currency and Finance 2023-24*. Mumbai: RBI.
- 18- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- 19- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- 20- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton.
- 21- Timmer, C. P. (2010). *Food Security in Asia and the Pacific*. Manila: Asian Development Bank.
- 22- United Nations. (2023). *World Economic Situation and Prospects 2023*. New York: United Nations.
- 23- World Bank. (2023). *Commodity Markets Outlook*. Washington, DC: World Bank.
- 24- World Bank. (2024). *India Development Update*. Washington, DC: World Bank.
- 25- World Bank. (2024). *Food Security Update*. Washington, DC: World Bank.
- 26- Reserve Bank of India. (2024). *Supply Chain Dynamics and Food Inflation in India*. RBI Bulletin, Mumbai.
- 27- Government of India. (2024). *Agricultural Statistics at a Glance 2024*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi.
- 28- Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. (2024). *Annual Report 2023-24*. Government of India, New Delhi.

- 29- NITI Aayog. (2023). *National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review 2023*. Government of India, New Delhi.
- 30- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. Rome: FAO.
- 31- Reserve Bank of India. (2025). *Annual Report 2024-25*. Mumbai: Reserve Bank of India.